

संपादक की कलम से

नीतीश ने पाला बदलकर विपक्षी एकता की जड़ें हिला दीं

पांचिर बिहार में नीतीश और उनके जदयू ने विपक्ष के गठबंधन का आई.ज.एन.ज.डी.आई.ए. से अपना नाता तोड़ लिया। नीतीश कुमार विपक्ष ने जो के गठबंधन इंडिया अलायंस के सुत्राधार रहे हैं। उन्होंने ही भाजपा के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट करने की शुरूआत की। एक दूसरे के धूरों पर रोधी दलों को एक साथ बैठाया, ऐसे में उनके पलटी मार देने से इस टिकटबंधन को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। नीतीश को बिहार के लटू राम कहा जाता है, पलटू राम इस बार पलटीमार कर विपक्ष के काना की जड़ ही हिंला गए। उनके भाजपा के साथ जाने से जनता ने एक सदेश गया कि ये एक सिद्धांत का नहीं स्वार्थ का था। नीतीश विद्यास विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का था। उसका सफल होने और अपने प्रदेश में हुए घटनाक्रम के कारण वे अपने खुयमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए भाजपा के साथ चले गए। नीतीश कुमार ने खुद विपक्षी दलों को एकजुट करने में पिछले कई माहों की अपी महनत की थी। उन्होंने शुरूआत में ऐसे दलों को कांग्रेस के साथ-साथ दूसरे के कांग्रेसी दलिल की तो गढ़ल साधी और उनकी पार्टी व

ठाठन म कामयाब हासल का जा रहुल नाधा आर उनका पाटा कर सवाल उठाते रहे थे। नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल में सरकार चल गई ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और माजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को साथ लाने में कामयाब रहे। पटना में गठबंधन की पहली बैठक कराने को भी उनकी कामयाब राजनीति दर्शाता है। दूसरी बैठक के बाद से ही नीतीश कुमार के असहज होने वाली चर्चा शुरू हो गई। तब कांग्रेस फ्रंट फुट पर आती दिखी। रिपोर्टों वाकिया किया गया कि गठबंधन संयोजक न बनाए जाने से वो नाखुश है। इसकी अपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने को लेकर भी मीडिया रिपोर्टों वाला हा गया कि नीतीश कुमार ने शिकायत की थी कि उनसे सलाह नहीं गई। उनका मानना था कि इंडिया में ऐंडीए आता है, इसलिए उन्होंने अपनी नाराजगी की रिपोर्टों को खारिज कर दिया था।

वावर का बाजपा के अगुवाइ वाल मठबंधन एनडीए के साथ जान के सला करने के बाद खुद नीतीश कुमार ने अपनी असहजता को सामायां किया कि ह्यूक्ल ठीक नहीं चल रहा था। दरअस्ल यह चाहते थे कि उन्हें गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए और उन्हें 19 दिसंबर को हुई ईंडिया गठबंधन की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष लिलकार्जुन खरगे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सुझाए जाने पर होने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी किंतु उनका गठबंधन से मन उचट लगा। उन्हें लगने लगा कि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन पर हावी होना चाहता था। राहुल की भारत न्याय यात्रा ने इस विद्रोह में आग में धी का कान न्या। कायदे ये यात्रा उन प्रदेशों में निकलनी चाहिए थी, जहां कांग्रेस ने सरकार है। विपक्षी दलों के सरकार वाले प्रदेश में स्थानीय दल कर्जी से उसे साथ लेकर ये यात्रा की जानी चाहिए थी किंतु ऐसा नहीं आ। बंगाल में यात्रा पहुंचने पर ममता बनर्जी को लगा कि उनके मजोर करने के लिए उनके प्रदेश से यात्रा निकाली जा रही है। जरा रासी बात पर नाराज होने वाली ममता इस यात्रा के बंगाल में आते ही छल गई। उन्हें लगा कि राहुल और कांग्रेस इसके माध्यम से उनके मजोर करना चाहती है। सो उन्होंने बंगाल में अकेले अपने बूते प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। यात्रा बिहार में भी आनंद रहा। बिहार में नीतीश को अपने सहयोगी रहे लालू यादव के रवैये रहा कि वह उनकी पार्टी में तोड़फोड़ करना चाहते हैं। दरअस्ल नीतीश कुमार के इस पलट के पीछे उनकी पार्टी में चल रही राजनीति थी नीतीश कुमार को पिछले महीने इसकी भनक तब लगी जब पार्टी के कुछ अधिकारी ने पार्टी लाइन से हटकर मीटिंग की थी। इसके साथ ही नीतीश तेजी दिखाते हुए ललन सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा या था तथा खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे। तभी से कायास लगा रहे थे कि उनकी पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और उनके और लालू यादव के रासे अलग होने वाले हैं। लालू यादव नीतीश प्रबाव दिए थे कि वे तेजस्वी को मुख्य मंत्री बनाए। नीतीश कुमार वेवर को बिहार के महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी की अगुवाले एनडीए का हाथ थाम लिया। दोनों ने मिलकर सरकार बना ली पथ भी हो गई। ये भी तै हो गया कि जदयू और भाजपा मिलकर बिहार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का प्रयास था कि वह विपक्ष कंकाली तोड़ सक, सो वह उसमें कामयाब हो गई। उसने बड़ा सोम प्रमुखकर ये निर्णय लिया। भाजपा को नीशीथ के साथ लेने से लोकसभा नीतीश में बिहार में फायदा ही होगा नुकसान नहीं। दूसरे विपक्ष में टूटकर वह इस टूट का फायदा उठाने में लग गई है। उसने प्रचार शुरू कर दिया कि ये स्वार्थ का गठबंधन है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के तुरंत दो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ह्याँडी अलायंसह सैद्धांतिक रूप से असफल हो चुका है। नड्डा ने प्रकारों से कहा, हम पहले भी ह चुके हैं कि ईंडिया अलायंस अवित्र, गैरवैज्ञानिक है और यह ज्यादा न तक नहीं चलेगा। और भारत जोड़ो यात्रा जो बेनीजा समाप्त हुआ और अभी की इनकी अन्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा और इंडियालायंस है, यह सैद्धांतिक तौर पर विफल हो चुका है।

आत्मनिर्भर, स्वतंत्र राष्ट्र सुनहरे और स्वाभिमानी भविष्य को जन्म देता है

राधोन सपने हूं सुख नाहीं" यह लोकात्कि हर स्वाभिमानी आदमी और स्वतंत्रता प्रेरणा की अपेक्षा को याद रहती है। स्वावलंबन या आत्मनिर्भरता ही मनुष्य को स्वाधीन बनाने की अपेक्षा देती है। आत्मनिर्भरता की स्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपनी सुविधा के लिए दूसरों की तरफ मुँह ताकने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी अति आवश्यक है एक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी जनता को अपनी क्षमता व अधिकारों को देने की जरूरत। नुसार सारी सुविधाएं तथा अन्य जीवन उपयोगी साधन उपलब्ध करा सकता है। भारत द्वारा देश के बाद हरित क्राति सातवें दाक के प्राप्तव के बाद ही खाद्यानन के मामले अत्यनिर्भर बन सका, इसके साथ ही भारत में खुशहाली की स्वाभाविक तौर पर वृक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि "एक राष्ट्र की शक्ति उसका अत्यनिर्भरता में है दूसरों से उधार लेकर काम चलाने में नहीं", पाकिस्तान की स्थिति अल्फुल ऐसी ही है वह अभी तक स्वतंत्रता के बाद से 75 वर्ष के बाद भी संपूर्ण रूप अत्यनिर्भर नहीं हो पाया है, वह कर्ज से डूब गया है और अपने देश में खर्च चलाने वाले अपने अपरीदुनिया से उधार मांगते हुए घूम रहा है। पाकिस्तान आत्मनिर्भर नहीं होने वाला है उधार की जिदी जीने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जबकि भारत देश विजाती नालौर्जी, मेंडिल ल साइस, इंजनियरिंग और कृषि सेवा, खनिज, रेंजरिंस इसीर में पूर्णता अत्यनिर्भर होकर विकसित देशों के बराबर खड़ा हुआ है। यह देशवासियों और देश विकास तथा और उसके नागरिकों की जिंदगी की जिजीविष है जिससे वह संघर्ष करके देश बढ़ाता है। इतिहास गवाह है कि किसी भी महान लेखक को महान बनने तक निरंतर अनन्त कर किताबें लिखने का श्रम करना पड़ा एवं आत्मनिर्भरता की स्थिति में विचार कर अपने विचारों को लिपिबद्ध करना पड़ा तब जाकर वह महानता की श्रेणी को प्राप्त करका। इसी तरह कोई छात्र अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे स्वध्ययन करना होगा। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में भी मनुष्य को आत्मनिर्भर होकर अनन्त कर दीक्षित सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी।

भारत देश भारत भी आजादी के बाद से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रित हुआ आज तक यह था कि वह विश्व में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। तभी वह अपुरुषों के जीवन से भी हमें आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंबन की शिक्षा मिलती रहती है। महात्मा गांधी अपना कार्य स्वयं किया करते थे। गोसामी तुलसीदास जी ने भी "दैवत आलसी" पुकारा है, तब जाकर उनकी जिदी पटरी पर आई और हमें परिश्रम का अन्य निर्भर होने की शिक्षा प्रदान की थी। दूसरों पर निर्भरता हमें दूसरों का अनुसर करने के लिए मजबूर करती है। दूसरों पर निर्भर होने से हमें के अनुरूप ही जीवन जीना लिए बाध्य होना पड़ता है। पराधीनत हमारा आत्मविश्वास सुजनशीलता सोचने वाले व्यक्ति को नष्ट कर देती है। गुलामी एक अभिशाप होती है, आत्मनिर्भरता की कमी है।

साङ्गेदारी के शिखर पर भारत-फ्रांस

अरविंद जयतिलक (वरिष्ठ
पत्रकार)

75 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनैल मैक्रों की भारत यात्रा ने दोनों देशों के रिश्ते को मिठास से भर दिया है। राष्ट्रपति इमैनैल मैक्रों की भारत की यह तीसरी यात्रा है। इससे पहले वे वर्ष 2018 में भी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने थे। दोनों देशों के बीच कितना मधुर संबंध है, वह इसी से समझा जा सकता है कि 1976 से लेकर अब तक 5 बार फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ा चुके हैं। इस समय दोनों देश रणनीतिक साझेदारी की 25 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

इस अवसर पर प्रधानमंत्रा मादा और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच कई विषयों पर सहमति बनी है जो दोनों देशों के लिए बेहद फायदेमंद है। फ्रांस की ओर से भारतीय छात्रों के शेंगेन वीजा की वैधता 5 साल का एलान किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भारतीय छात्रों को फ्रांस में तीन महीने से लेकर केवल एक साल तक ही रहने की अनुमति थी। दोनों देशों के बीच पढ़ाई से लेकर रोजगार के मसले पर बातचीत हुई। दोनों देश युवा पेशेवर योजना की घोषणा की है जिसके तहत 18 वर्ष से 35 वर्ष के युवाओं को एकदूसरे के देश में कमाई के रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप, सैटेलाइट लांच के लिए नए स्पेस इंडियन लिमिटेड और परियन स्पेस के बीच एमओयू हुए हैं। टाटा और एयरबस स्थानीय कंपनी के साथ मिलकर 125 हेलीकॉप्टर बनाएंगे। दोनों देशों के बीच विज्ञान, तकनीक, स्वास्थ्य सेवा सहयोग, कृषि समेत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफ्राम्स के मसले पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ओलांपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत के इरोड का समर्थन किया है। और करें तो मौजूदा समय में दोनों देशों के संबंध शिखर पर हैं। याद होगा जब गत वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस के

सर्वोच्च सम्मान हैंग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनरल से सम्मानित किया।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी बेहद उत्साहित दिखे और उन्होंने कहा कि विश्व इतिहास में एक दिग्जे, भविष्य में एक निर्णयिक भूमिका निभाने वाला, रणनीतिक साझेदार एक मित्र का स्वागत करने पर उन्हें गर्व है। याद होगा जब 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तब उससे नाराज होकर दुनिया के ताकतवर मुल्क भारत पर प्रतिबध थोपा। तब फ्रांस ने भारत के साथ कंधे जोड़ते हुए रणनीतिक समझौते को व्यापक आयाम दिया। फ्रांस लगातार भारतीय सेना को लड़ाकू जेट व पनडुब्बियों समेत साजो-समान की आपूर्ति कर रहा है।

गैर करें तो 2018 के बाद से फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है। मौजूदा समय में भारत अपनी कुल रक्षा आयात का तकरीबन 29 फीसदी फ्रांस से करता है। दोनों देशों के बीच बढ़ती निकटता ने कारोबारी, रणनीतिक और सामरिक कुट्टीति को नए क्षितिज पर पहुंचा दिया है। दोनों देश एकदूसरे के सैनिक अड्डे का इस्तेमाल और वहां

अपने युद्धोपाते रखने के अलावा उर्जा, तस्करी, आव्रजन, शिक्षा, रेलवे, पर्यावरण, परमाणु, आतंकवाद और अंतरिक्ष मामलों में मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस आत्मनिर्भर भारत मुहिम का साझीदार बनने के साथ-साथ 2025 तक बीस हजार भारतीय छात्रों को अपने यहां पढ़ाई का सुअवसर उपलब्ध कराने का एलान पहले ही कर चुका है। दोनों देशों के बीच यूपीआई को लेकर भी सहमति बन चुकी है।

विंगत 25 वर्षों के दरम्यान दोनों देशों के बीच साझेदारी और समझदारी का ही परिणाम है कि आज भारत में विदेशी निवेश के लिहाज से फ्रांस तीसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन चुका है। भारत में 1000 से अधिक फ्रांस की कंपनियां काम कर रही हैं और सभी कंपनियों का संयुक्त टर्नओवर तकरीबन 30 अरब डॉलर से अधिक है। विंगत ढाई दशकों में भारत-फ्रांस संबंध को एक नया आयाम मिला है और दोनों देश राजनीतिक, आर्थिक व सामरिक संबंधों में बेहतरी के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। फ्रांस के नेतृत्व के दृष्टिकोण में बदलाव के साथ-साथ कछु द्विष्पक्षीय बाध्यताओं ने भी दोनों

सशक्त भारत का आधार है कानूनों का सरलोकरण

अवसर है भारतीय न्याय प्रणाली की कमियां पर मंथन करते हुए उसे अधिक चुस्त, त्वरित एवं सहज सुलभ बनाना। मतलब यह सुनिश्चित करने से है कि सभी नागरिकों के लिये न्याय सहज सुलभ महसूस हो, वह आसानी से मिले, जटिल प्रक्रियाओं से मुक्त होकर सस्ता हो। इस दृष्टि से यह अकलित उपलब्धियों से भरा-पूरा अवसर भारत न्याय प्रक्रिया को एक नई शक्ति, नई ताजगी, और नया परिवेश देने वाला साबित हो रहा है। क्योंकि आजादी के अमृतकाल में पहुँचने तक भारत की न्याय प्रणाली अनेक कंटिली झाड़ियों में उलझी रही है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था का छिपानेषण करें तो हम पाते हैं कि

न्याय देने की उम्मीद करना उचित
नहीं हो सकता है। विधि आयोग की
सिफारिश के अनुसार इन पदों की
संख्या में बढ़िया किया जाना चाहिये।
सुप्रीम कोर्ट में जजों के खाली पद
भरने का काम हुआ है, लेकिन
हाईकोर्टों में अभी भी काफी पद
खाली पड़े हैं। डिपार्टमेंट ऑफ
जस्टिस की वेबसाइट पर उपलब्ध
आंकड़ों के मुताबिक देश के सभी
25 हाईकोर्टों में जजों के कुल
1,114 पद मंजूर हैं, लेकिन इन
कोर्टों की मौजूदा न्यायाधीशों की
संख्या 784 है यानी हाईकोर्टों में
जजों के 330 पद खाली हैं।

न्याय प्रणाली में आमूल-चूल-
परिवर्तन, परिवर्त्तन जरूरी है और

खड़ग का आशका और मोदी का डंका

अंग्रेस अध्यक्ष श्री मलिकार्जुन खड़गे को आशंका है कि यदि इस साल होने वाले चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फिर आ गए तो ये देश के लिए आखिरी हाँगे, व्यक्ति इसके बाद मोदी जी स्वयंभू हो जायेंगे। यानि मोदी जी रुस के राष्ट्रपति या उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जॉंग या चीन के राष्ट्रपति शी षिंग के रास्ते पर जदेश में तानाशाही थोप देंगे। खड़गे देश के वरिष्ठ नेता हैं। वे प्रधानमंत्री मोदी जी से भी और अनुभव में बड़े हैं इसलिए उनकी आशंका को हल्के में नहीं लिया जा सकता की राजनीति में पिछले एक दशक से जो उत्पाटक हो रही है, उसकी वजह से आशंकाएं जन्म लेती हैं और ये बहुत स्वाभाविक हैं। जो आशंका देश की सबसे राजनीतिक पार्टी के मन में है वही आशंका इस देश के आम आदमी के मन में भी जरूरी नहीं है, भले ही कांग्रेस की ओर खड़गे जी की आशंका मिलू न हो। निश्चिय देश लोकतंत्र से एक तंत्र की ओर बढ़ रहा है। भारतीय लोकतंत्र पूर्व में इस तरघटनाक्रम से कभी नहीं गुज़रा। 1975 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक बार लोकों को बंधक बनाने का प्रयास करते हुए देश में आपातकाल लगाया था किन्तु उसकी उन्होंने से ज्यादा नहीं रही। जनता ने वापस लोकतंत्र की बहाली कर दी थी, ले

आज स्थितया एकदम भूल है।
भारत में आज लोकतंत्र को चुनीती देने के लिए किसी तरह का आपातकाल नहीं लगा गया है लेकिन सरकार की जो तंत्रिविधियाँ हैं वे आपातकाल से भी जायदा खतरनाक भयावह हैं। सरकार ने एक दशक में तमाम संवेदनिक संस्थाओं को बंधुआ बना लिया उन्हें बधिया [नसंबंदी] कर दिया है। आम जनता को धर्म का डबल डोज देने का हिस्टीरिया 'ऐदा' करने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। राजनीति में तोड़फोड़ का ढारा इसी दशक की देन है। जनदेश की अधिज्ञाया उड़ने का नया कीर्तिमान इसी दशबन्धा है। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र के बाद बिहार में ये खेल होते पूरी दुनिया देख रही है। इस खेल को रोकने वाला नहीं है। न सविधान और न जनता। सबके सब असहाय आ रहे हैं।
देश की आजादी की और सविधान की स्थापना की हीरक जयती वर्ष को देश अमृतकाल कहा गया लेकिन अप्रत पार में विष भरकर दे दिया गया और किसी को कान खंबर भी न हुई। अदावत की राजनीति के बलते समझे विषक को लंगड़ा - लूला के द्वारा कर्मी छिपायाएँ तो उसका दिल और कर्मी प्रत्यक्षमें कुर्सीपोता विष जा

क लै ए कहा बिनाष्णा का सहारा लिया त कहा पट्टुरामा का इसमाल किया जा है। हालाँकि ये सब निराश करने वाला घटनाक्रम है किन्तु जब कोई कुछ कर नहीं पाते तो इसे खुशी-खुशी रखीकर कर लेना ही पहला और आत्म विकाप लगता है, किन्तु देश की जनता ने अलग-अलग समय में मुगालों और अंग्रेजों की दासता को झ़िला लिया जाना चाहिए। इतनी आसानी से देश में तानाशाही को अपना शिकंजा नहीं कसने देगी। ये तथ्य है कि तानाशाही दबे पांव आती है, लेकिन उसकी आहट सुने वाले सुन ही है। आज खड़ग साहब ने, उनकी काग्रेस ने सुनी है कि कल पूरा देश इस आहट को सुन देश यानि आम जनता यदि अपने वोट की ताकत से तानाशाही को नहीं रोकेगी तो काँइ दूसरा रास्ता है भी नहीं। वोट का हथियार भी मानव सृजित मरीनों ने मोथारा दिया है। चुनाव की प्रक्रिया दृष्टिं और अविश्वसनीय हो चुकी है। जनता जनादेश से बदलना भी चाहे तो बदल नहीं सकती। बिहार इसका ताजा उदाहरण है। बिहार की जनता ने जनादेश दिया था उसकी बिजियां धर्मपरायण भाजपा और धर्मनिरपेक्षता की देने वाली जेडीयू ने मिलजुलकर उड़ा दी हैं। इन हरकतों के खिलाफ जनता कहाँ जाएगी? इस तरह के भयोकताविक किंवदकालों को योजने में असमर्पण है और अपनी

जारी करा इसके बाद उत्तरांशनक छापवालाना का रोकना जरूरी हआ। उकेरा के राम मंदिर में इस तरह के मामले सुने नहीं जाते। वहाँ सिर्फ जयकारे लगाए जा अयोध्या में मंदिर सरकारी है इसलिए ख्वाभाविक रूप से वहाँ विराजे रामलला भी सके ही पक्षकर हैं।

कुल मिलाकर स्थिति गंभीर है। अब लोकतंत्र की लड़ाई गैर भाजपा दलों के साथ ही जनता को ही लड़नी पड़ेगी। यदि जनता चाहती है कि -देश को भाड़ में जाने दिया तो जाने दिया जाये। जनता खुद भुतोंगी। और यदि जनता चाहती है कि जो देश 1947 में बनाने के लिए मिला था उसे ही बचाया और बनाया जाये तो फिर सर्वे जनता के साथ खड़े हो जाना चाहिए। जनता से बड़ा कोई नहीं है। न धर्म, न कानून न कोई तानाशाह। ये मेरी मान्यता है। इसका खड़ोंगी की ओर कांग्रेस की मान्यता से लेना-देना नहीं है। क्योंकि एक आम आदमी किसी गर्बधन का हिस्सा नहीं होता अपनी पसंद से अपने लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार अभी तक तो हासिल कर ल जब नहीं होगा, तब की बात और है। तब मुम्किन है कि हम और आप इस पर बात ही न कर पाएं।

विदेश संदेश

इमरान खान और महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल की सजा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में आज मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान और पार्टी के नेता एवं पूर्व विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। राजलंगिंडी के स्पेशल कार्ट के अंतुल हसन जुल्करेन के नेता अंबुल जेल में अंदियाला जेल में इसका एलान किया।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और कुरैशी की बौजूदी में जेज ने यह फैसला सुनाया। पिछले साल से ही इस केस के सुनवाई अंदियाला जेल में चल रही है। उल्लेखीय है कि पाकिस्तान में अठ फैसले को आम चुनाव हैं। ऐसे में दिन पहले आया यह फैसला इमरान खान के राजनीतिक करियर के



लिए खतरनाक हो सकता है।

कीर्वड में लिखा गया संदेश।

साइफर का मतलब होता है सीक्रेट

होता है। यह डिप्लोमेटिक कम्पनिकेशन का हिस्सा होता है। दो देशों की बीच होने वाली कई तरह की बातचीत को गुप्त रखा जाता है।

संघीय जांच एंजेंसी के आरोप पत्र में कहा गया है कि इमरान ने इस संदेश को वापस नहीं किया। पीटीआई लंबे समय से कह रही है कि इस संदेश में इमरान को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से धमकी दी गई थी। इमरान और कुरैशी चुनाव से पहले जेल में बदल हैं। इमरान खान की उम्मीदवारी भी खारिज हो चुकी है। कुरैशी को जरूर चुनाव लड़ने की छूट मिली है लेकिन अजांकी की सजा का मतलब है कि दोनों अगले पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

पाकिस्तान में चुनाव से पहले हिंसा का दौर, कराची में गोलीबारी में 1 की मौत, 3 घायल

कराची। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले कराची में पिछले कुछ दिनों में चुनावी हिंसा बढ़ गई है। इस तहजीब से गद्दीय और प्रातीय विधायक सभा सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे दलों के बीच पहले से ही कई झड़पें हो चुकी हैं। ताजा घटनाक्रम में सोमवार का नाजिमान में हिंसक झड़प हुआ, जिसमें पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के कार्यकर्ताओं के साथ गोलीबारी के दौरान मुकाबिला कीमी मूल्यें (एम्ब्यूएम पाकिस्तान) के

एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले रविवार को विलापन इलाके में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी की एक चुनावी लैंगी पर पुलिस की भारी टक्कियों द्वारा चुनावी लैंगी पर नियमित घटनाएँ हुईं, जिसमें पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के कार्यकर्ताओं के साथ गोलीबारी के दौरान मुकाबिला कीमी मूल्यें (एम्ब्यूएम पाकिस्तान) के

कराची - जो पाकिस्तान का वित्तीय केंद्र ही है, पर पीपीपी के गढ़ के लिए एक चुनावी की सामना करना पड़ रहा है, जोकि आगामी चुनावों में विभिन्न पार्टियों जमकर प्रतिस्पर्धा कर रही है। बिलावल जरदारी भूमि के नेतृत्व वाली पीपीपी की सिंधु और टक्कियों द्वारा चुनावी लैंगी पर पुलिस की भारी टक्कियों द्वारा चुनावी लैंगी पर पकड़ तब भी बनी हुई है। गैंग के गोले देंगे और जबरन तिरत-बितर कर दिया। इस उपद्रव में कुछ सरकार बनाई थी और अंवश्वार प्रस्ताव के बाद 2022 में शाहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन

कराची - जो पाकिस्तान का वित्तीय

कराची - जो पाकिस्तान का वित्तीय केंद्र ही है, पर पीपीपी के गढ़ के लिए एक चुनावी की सामना करना पड़ रहा है, जोकि आगामी चुनावों में विभिन्न पार्टियों जमकर प्रतिस्पर्धा कर रही है। बिलावल जरदारी भूमि के नेतृत्व वाली पीपीपी की सिंधु और टक्कियों द्वारा चुनावी लैंगी पर पुलिस की भारी टक्कियों द्वारा चुनावी लैंगी पर पकड़ तब भी बनी हुई है। गैंग के गोले देंगे और जबरन तिरत-बितर कर दिया। इस उपद्रव में कुछ सरकार बनाई थी और अंवश्वार प्रस्ताव के बाद 2022 में शाहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन

कराची - जो पाकिस्तान का वित्तीय

कराची - जो पाकिस्तान का वित्तीय